मूल्य 1 रु.
वर्षः 10 - अंक : 277, मुंबई, शुक्रवार, 15 जनवरी, 2021 ■ RNI.NO. MAHHIN/2010/34146 ■ संपादकः दिलशाद एस. खान

दैनिक मुंबई हलचल

भारत सरकार द्वारा विज्ञापन हेतु मान्यता प्राप्त ®
अब हर सच होगा उजागर

कोरोना पॉजिटिव मरीज भी डाल सकेंगे वोट

महाराष्ट्र राज्य चुनाव आयोग का अहम फैसला

संवाददाता

मुंबई। कोरोना पॉजिटिव मरीज और क्वारंटीन सेंटर में इलाज करा रहे मरीज भी अब वोट डाल सकेंगे। कोरोना पॉजिटिव मरीजों को मतदान खत्म होने की आधा घंटा पहले तमाम एहतियातन उपायों के साथ वोट डालने की सुविधा दी जाएगी। राज्य चुनाव आयोग ने यह सुविधा स्थानीय निकाय चुनाव के लिए दी है। यह जानकारी बुधवार को राज्य चुनाव आयुक्त यूपीएस मदान ने दी है। मदान ने कहा कि स्थानीय स्वराज्य संस्थाओं के चुनावों के लिए राज्य चुनाव आयोग ने 15 दिसंबर, 2020 को मार्गदर्शक सूचनाएं जारी की थीं। **(शेष पृष्ठ 3 पर)**

खतरे में धनंजय मुंडे की कुर्सी?

शरद पवार ने रेप के आरोपों को बताया गंभीर

फैसला जल्द

मुंबई। महाराष्ट्र के सामाजिक न्याय मंत्री धनंजय मुंडे के खिलाफ एक महिला द्वारा लगाए गए बलात्कार के आरोपों को गंभीर बताते हुए राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रमुख शरद पवार ने गुरुवार को कहा कि पार्टी इस मुद्दे पर चर्चा करके शीघ्र फैसला लेगी। **(शेष पृष्ठ 3 पर)**

भाजपा नेता कृष्ण हेगड़े बोले-यह महिला 2010 से मुझे भी परेशान कर रही

इस बीच, भाजपा नेता कृष्ण हेगड़े ने बृहस्पतिवार को दावा किया कि महाराष्ट्र के मंत्री व राकांपा नेता धनंजय मुंडे पर दुष्कर्म का आरोप लगाने वाली महिला पिछले कई साल से उन्हें भी परेशान कर रही है। अंबोली पुलिस को लिखे पत्र में पूर्व विधायक ने कहा कि आरोप लगाने वाले महिला 2010 से ही उन्हें फंसाने का प्रयास कर रही है।

राकांपा प्रमुख शरद पवार ने धनंजय मुंडे पर कड़ी कार्रवाई का दिया संकेत

मुंडे ने कहा कि महिला का दावा उन्हें ब्लैकमेल करने की साजिश का हिस्सा है

बढ़ सकती हैं नवाब मलिक की मुश्किलें

दामाद के ड्रग सिंडिकेट में शामिल होने का शक?

समीर खान को 18 जनवरी तक भेजा गया एनसीबी की कस्टडी में, ड्रग्स मामले में हुई है गिरफ्तारी

संवाददाता

मुंबई। महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री नवाब मलिक के दामाद समीर खान को अदालत ने 18 जनवरी तक नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की कस्टडी में भेज दिया है। समीर खान को बीती रात एनसीबी ने 10 घंटे से ज्यादा चली पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया है। समीर पर ड्रग पेडलर करन सजनानी के साथ ड्रग्स के धंधे में शामिल होने का आरोप है। कैबिनेट मंत्री नवाब मलिक के दामाद समीर खान को एनसीबी द्वारा गिरफ्तार किए जाने के बाद उनकी मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। **(शेष पृष्ठ 3 पर)**

दैनिक मुंबई हलचल
अब हर सच होगा उजागर

हमारी बात

ऐतिहासिक अभियान

भारत जैसे विशाल देश में कोरोना टीकाकरण की शुरुआत सुखद और ऐतिहासिक है। आज से साल भर पहले लोग कोरोना के बारे में ठीक से जानते भी नहीं थे, लेकिन आज इस बारे में लगभग सभी को पता है। यह अपने आप में इतिहास ही है कि इतनी जल्दी किसी रोग के टीके का न केवल निर्माण हुआ है, बल्कि वह देश के लगभग हर जिले में पहुंच भी गया है। यह अवसर किसी उत्सव से कम नहीं है। पहले चरण में टीके का खर्च पूरी तरह से केंद्र सरकार उठा रही है, तो कोई आश्चर्य नहीं। पहले चरण में करीब तीन करोड़ अग्रिम पंक्ति के कोरोना योद्धाओं को टीका लगाया जाएगा। ताजा आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं, लेकिन अक्तूबर महीने में ही 500 से ज्यादा डॉक्टर कोरोना की वजह से शहीद हुए थे। एक अंदाजा लगाया जा सकता है कि शहीद होने वाले कुल कोरोना योद्धाओं की संख्या चार अंकों में होगी। जब देश के तमाम अग्रिम पंक्ति के योद्धाओं को टीका लग जाएगा, तब कम से कम डॉक्टर और चिकित्साकर्मी बेहिचक सेवा कर सकेंगे। देश में हर्ड इम्युनिटी अर्थात सामूहिक रोग प्रतिरोधक क्षमता के निर्माण में अग्रिम पंक्ति के योद्धाओं का टीकाकरण बुनियाद है। यह जरूरी है कि 16 जनवरी से शुरू हो रहे इस चरण में टीकाकरण को पर्याप्त कामयाबी मिले। बहुत से ऐसे योद्धा होंगे, जो टीका लेना पसंद नहीं करेंगे, लेकिन उन्हें आश्वस्त करते हुए इस चरण के टीकाकरण को कामयाब बनाना होगा। लोगों की भी निगाह इस अभियान की सफलता पर टिकी है। अभी भी कुछ विपक्षी पार्टियों के नेताओं को टीके की गुणवत्ता पर भरोसा नहीं हो रहा है। ऐसे में, भाजपा शासित राज्यों को इस अभियान में सोलह आना कामयाब उतरना होगा। मामला पूरी तरह से विश्वास का है, लोगों का विश्वास सशक्त करना जरूरी है। यह काम तभी बेहतर ढंग से हो सकेगा, जब डॉक्टर स्वयं टीका लेने के लिए आगे आएंगे। डॉक्टरों को न केवल टीका लेने में आगे रहना है, उन्हें इस अभियान को गुणवत्तापूर्ण ढंग से पूरा भी करना है। तमाम सावधानियों के साथ पहला चरण पूरा होना चाहिए और इस चरण में रह जाने वाली त्रुटियों से सीखना चाहिए। इस चरण के बाद संभव है, अगले चरण में टीके के लिए लोगों को भुगतान करना पडे। करीब छह राज्यों ने अपने यहां लोगों को मुफ्त टीका लगाने का वादा किया है, लेकिन बाकी अनेक राज्य हैं, जो टीका का खर्च उठाने के लिए तैयार नहीं होंगे। स्वाभाविक ही चूंकि टीका महंगा है, इसलिए कुछ सरकारें मुफ्त टीके की घोषणा से बच रही हैं। जो टीका सरकारों को महंगा लग रहा है, वह आम लोगों को कितना महंगा लगेगा, इस बारे में सोच लेना चाहिए। एक और महत्वपूर्ण संकेत यह है कि शायद सरकार लोगों को टीकों में से किसी एक को चुनने का अधिकार नहीं देने पर विचार कर रही है। मतलब जिसे जो टीका दिया जाएगा, उसे वही टीका लेना पड़ेगा। यहां एक अंतर करना पडेगा, यदि टीकों की कीमत समान नहीं रहेगी, कम या ज्यादा रहेगी, तो लोगों को चुनने का विकल्प मिलना चाहिए। लोगों से टीका चयन का अधिकार तभी छीनना चाहिए, जब टीकों की गुणवत्ता और कीमत में एकरूपता हो। टीकाकरण में हर स्तर पर पारदर्शिता और न्याय सुनिश्चित करते हुए ही आगे बढ़ा जा सकता है। साथ ही, टीके के आने का अर्थ यह नहीं कि बचाव या सावधानियों से हम मुंह चुराने लगें।

कृषि कानूनों पर अब आगे क्या?

केंद्र सरकार के बनाए तीन कृषि कानूनों और किसान आंदोलन में अब आगे क्या होगा? सुप्रीम कोर्ट ने चार लोगों की एक कमेटी बना दी है, जिसे किसानों की शिकायतें सुननी हैं और संभव है कि सरकार को भी इसमें अपना पक्ष रखने का मौका मिले। आठ हफ्ते में कमेटी को अपनी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को सौंपनी है। सवाल है कि अगर किसान इस कमेटी के सामने नहीं जाते हैं, जैसा कि उन्होंने ऐलान किया है तो फिर क्या होगा? क्या कमेटी सिर्फ सरकार का पक्ष सुन कर अदालत को रिपोर्ट दे देगी और अदालत उस पर कोई फैसला सुना देगी? वैसे भी कमेटी के सारे सदस्य अपना फैसला पहले ही जाहिर कर चुके हैं। चारों सदस्यों ने किसी न किसी मंच पर कृषि कानूनों की तरफदारी की है, इन्हें किसानों के लिए फायदेमंद ठहराया है और इन्हें वापस लेने का विरोध किया है। अब ऐसा तो है नहीं कि सुप्रीम कोर्ट की ओर से पंच परमेश्वर बनाए दिए जाने के बाद उनकी अंतरात्मा जग जाएगी और वे अचानक दूसरी बात करने लगेंगे। इसलिए सबको मालूम है कि वे अपनी रिपोर्ट में क्या लिखेंगे!

बहरहाल, किसान कमेटी के सामने जाएं या नहीं जाएं, सुप्रीम कोर्ट उन्हें इसके लिए मजबूर नहीं कर सकता है। इसी मामले की सुनवाई में खुद चीफ जस्टिस एसए बोबडे ने कहा है कि 'अगर किसान बेमियादी आंदोलन करना चाहते हैं करें, लेकिन जो भी व्यक्ति मसले का हल चाहेगा वह कमेटी के पास जाएगा'। इसका मतलब है कि किसान अगर सुप्रीम कोर्ट की बनाई कमेटी के जरिए समाधान नहीं चाहते हैं तो वे कमेटी के सामने नहीं जाने और अपना बेमियादी आंदोलन जारी रखने के लिए स्वतंत्र हैं। ध्यान रहे चीफ जस्टिस ने यह भी कहा है कि किसानों को शांतिपूर्ण आंदोलन करने का अधिकार संविधान से मिला है और अदालत उसमें कई रोक-टोक नहीं करेगी। सो, अगर किसान कमेटी के सामने नहीं गए और आंदोलन जारी रखा तो अदालत क्या करेगी? असल में देश की सर्वोच्च अदालत ने इस मामले में केंद्र के बनाए कानूनों की संवैधानिक वैधता की जांच करने की बजाय खुद को मध्यस्थ बना कर एक अजीबोगरीब स्थिति पैदा कर दी है। सुप्रीम कोर्ट संवैधानिक अदालत है और उसे शक्तियों के पृथक्करण सिद्धांत से न्यायिक समीक्षा का जो अधिकार मिला हुआ है वह संसद या विधानसभाओं के बनाए कानूनों की

संवैधानिकता और उसके न्यायिक पहलुओं की जांच के लिए है। अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के तीन जजों की बेंच ने केंद्र सरकार के 'सेंट्रल विस्टा' प्रोजेक्ट से जुड़े मामले में यह बात दोहराई थी। जजों ने कहा था कि सरकार के नीति बनाने के अधिकार में दखल देने की अदालत की कोई मंशा नहीं है, यह विशुद्ध रूप से संसद का काम है। लेकिन अब वहीं अदालत कानूनों की न्यायिक समीक्षा और व्याख्या की बजाय उन कानूनों से पैदा हुई स्थितियों में मध्यस्थ या उसे प्रभावित करने वाले की भूमिका में आ गई है।

ध्यान रहे सुनवाई के दौरान पंजाब सरकार की ओर से इसकी संवैधानिक वैधता का मुद्दा उठाया गया पर अदालत ने उस पर ध्यान देने की बजाय किसानों के आंदोलन पर फोकस किया। यह समझना मुश्किल है कि कानूनों की संवैधानिक वैधता जांचने की बजाय किसानों का आंदोलन अदालत के लिए इतनी चिंता का कारण क्यों है? यह भी कम हैरान करने वाली बात नहीं है कि अदालत ने कानूनों की संवैधानिकता पर कोई भी दलील सुने बगैर इसके अमल पर रोक लगा दी। यह पहली बार हुआ है कि सर्वोच्च अदालत ने संसद के बनाए किसी कानून के अमल पर बिना किसी सुनवाई के रोक लगाई है। अदालत ने अपने फैसले में कहा कि वह इतनी असहाय नहीं है कि सरकार के बनाए कानून पर रोक नहीं लगा सके। इसमें कोई संदेह नहीं है कि सरकार के बनाए किसी भी कानून पर रोक लगाना सुप्रीम कोर्ट के अधिकार क्षेत्र में आता है पर खुद सुप्रीम कोर्ट के दो जजों की बेंच पहले एक मामले में कह चुकी है कि जब तक कानून में किसी असंवैधानिकता का पता नहीं चलता है तब तक उस पर अंतरिम रोक नहीं लगाई जा सकती है। सवाल है कि बिना सुनवाई के असंवैधानिकता का पता कैसे चलेगा? यह भी हैरान करने वाली बात है कि सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार के बनाए कानूनों की संवैधानिकता पर विचार किए बगैर, सरकार के वकीलों की दलील सुने बगैर रोक लगा दी और सरकार खुश है! सरकार के वकीलों ने इस पर सवाल नहीं उठाए और न अदालत के सामने इसका विरोध किया और न इस बात पर जोर दिया कि कानूनों पर रोक से पहले इसके संवैधानिक पहलुओं की समीक्षा की जाए। उलटे सरकार के वकील भी किसान आंदोलन से लोगों को हो रही मुश्किलों और इसमें कथित तौर पर खालिस्तानी तत्वों के शामिल होने का मुद्दा उठाते रहे। तभी सवाल उठता है कि क्या सरकार भी चाहती थी कि अदालत ऐसा कोई फैसला दे, जिससे किसान आंदोलन को खत्म करने या कमजोर करने का मौका बने? अगर ऐसा है तो यह और भी चिंता की बात है क्योंकि इससे एक नई नजीर स्थापित होती है। इससे यह मैसेज बनता कि सरकार को बतौर कार्यपालिका, जो जिम्मेदारी निभानी थी वह अदालत ने निभाई है।

इस तरह अदालत ने संविधान में की गई शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत की अवहेलना की है और यह मैसेज दिया है कि अगर सरकारें किसी कार्यकारी विवाद का निपटारा नहीं कर पाती हैं तो उसे अदालती तरीके से निपटाया जा सकता है। इसके लिए अदालत ने संविधान के संरक्षण वाली भूमिका छोड़ कर मध्यस्थ वाली भूमिका अपनाई। पर उसमें भी ऐसा लग रहा है कि अदालत ने मध्यस्थता के सबसे बुनियादी सिद्धांत की अनदेखी की है। मध्यस्थता का सबसे बुनियादी सिद्धांत यह है कि जिस मुद्दे का निपटारा होना है उसमें शामिल सभी पक्ष मध्यस्थता के लिए सहमत हों। उनकी इस सहमति के बाद ही मध्यस्थों की नियुक्ति होती है। पर यहां तो किसान पहले से ही मध्यस्थता से इनकार कर रहे थे। उन्होंने कमेटी बनाने के केंद्र सरकार के सुझाव को भी ठुकराया था और अदालत से भी कह दिया था कि कमेटी उनको मंजूर नहीं है। उनका विवाद सरकार से है और वे समाधान भी सरकार से ही हासिल करेंगे। जब किसान संगठन मध्यस्थता के लिए, तैयार नहीं थे तो मामला वहीं खत्म हो जाना चाहिए था। पर अदालत ने उनकी सहमति के बगैर चार सदस्यों की कमेटी बना दी। कमेटी के सदस्यों के नामों पर भी सहमति बनाने का कोई प्रयास नहीं हुआ। तभी कमेटी बनते ही किसानों ने इसे खारिज कर दिया। उन्होंने दो टूक कहा कि यह सरकारी कमेटी है और इसके सारे सदस्य पहले ही कानूनों का समर्थन करते रहे हैं।

सरकार तुरंत पहल करे

सर्वोच्च न्यायालय की यह कोशिश तो नाकाम हो गई कि वह कोई बीच का रास्ता निकाले। सरकार और किसानों की मुठभेड़ टालने के लिए अदालत ने यह काम किया, जो अदालतें प्रायः नहीं करतीं। सर्वोच्च न्यायालय का काम यह देखना है कि सरकार या संसद ने जो कानून बनाया है, वह संविधान की धाराओं का उल्लंघन तो नहीं कर रहा है ? इस प्रश्न पर सर्वोच्च न्यायाधीशों ने एक शब्द भी नहीं कहा।

उन्होंने जो किया, वह काम सरकार या संसद का है या जयप्रकाश नारायण जैसे उच्च कोटि के मध्यस्थों का है। उसका एक संकेत अदालत ने जरुर दिया। उसने तीनों कृषि-कानूनों को फिलहाल लागू होने से रोक दिया। उसने सरकार का काम कर दिया। सरकार भी यही करना चाहती थी लेकिन वह खुद करती तो उसकी नाक कट जाती। लेकिन अदालत ने जो दूसरा काम किया, वह ऐसा है, जिसने उसके पहले काम पर पानी फेर दिया। उसने किसानों से बातचीत के लिए

चार विशेषज्ञों की कमेटी बना दी। यह कमेटी तो ऐसे विशेषज्ञों की है, जो इन तीनों कानूनों का खुले-आम समर्थन करते रहे हैं। इनके नाम तय करने के पहले क्या हमारे विद्वान जजों ने अपने दिमाग का इस्तेमाल जरा भी नहीं किया? क्या ये विशेषज्ञ ही इन तीनों अटपटे कानूनों के अज्ञात या अल्पज्ञात पिता नहीं हैं? हमारे न्यायाधीशों के भोलेपन और सज्जनता पर कुर्बान जाने को मन करता है। मंत्रियों से संवाद करने वाले किसान नेताओं को नीचे उतार कर अपने सलाहकारों से भिड़वा देना कौनसी बुद्धिमानी है, कौनसा न्याय है, कौनसी शिष्टता है? इस कदम का एक अर्थ यह भी निकलता है कि हमारी सरकार के नेताओं के पास अपनी सोच का बड़ा टोटा है।

इसीलिए उसने अपने मार्गदर्शकों के कंधे पर बंदूक धरवा दी। किसान नेताओं से संवाद करने के लिए सरकार को किसानों की सहमति से ऐसा मध्यस्थ-मंडल तुरंत बनाना चाहिए, जिसकी निष्पक्षता और ईमानदारी पर किसी को शक न हो। यदि इस काम में देरी हुई तो उसके परिणाम अत्यंत भयंकर भी हो सकते हैं। हमारा गणतंत्र-दिवस, गनतंत्र-दिवस में भी बदल सकता है। वह अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में जून 1984 में हुए हादसे को दोहरा सकता है। उससे बचना बहुत जरुरी है। किसानों ने अभी तक गांधीवादी सत्याग्रह की अद्भुत मिसाल पेश की है और अब भी वे अपनी नाराजी को काबू में रखेंगे लेकिन सरकार से भी अविलंब पहल की अपेक्षा है।

मुंबई: फर्जी कॉल सेंटर का भंडाफोड़, 11 लोग गिरफ्तार

संवाददाता

मुंबई। पुलिस ने मुंबई के घाटकोपर में फर्जी कॉल सेंटर का भंडाफोड़ कर ऋण बकाए के भुगतान के नाम पर कथित रूप से लोगों को ठगने के मामले में छह महिलाओं और पांच पुरुषों को गिरफ्तार किया है। एक अधिकारी ने बृहस्पतिवार को कहा कि 61 साल के एक मुंबई निवासी की शिकायत के आधार पर जांच के बाद पुलिस ने सोमवार को कॉल सेंटर पर छापा मारा और परिसर से 132 सिम कार्ड, 11 कम्प्यूटर और सात मोबाइल फोन बरामद किए। शिवाजी पार्क पुलिस थाने के एक अधिकारी ने बताया कि यह कॉल सेंटर पिछले साल अप्रैल से काम कर रहा था और आरोपी कोविड-19 वैश्विक महामारी का फायदा उठाकर उन लोगों को कथित रूप से ठग रहे थे, जिन्होंने बैंकों और अन्य वित्तीय कंपनियों से ऋण लिया है। अधिकारी ने बताया कि ये लोग उन कंपनियों के कर्मी बनकर उधार लेने वालों को फोन करते थे और उन्हें बकाया राशि की तुलना में बेहद कम राशि लेकर ऋण का निपटान करने का प्रस्ताव देते थे। एक शिकायतकर्ता ने पिछले महीने पुलिस

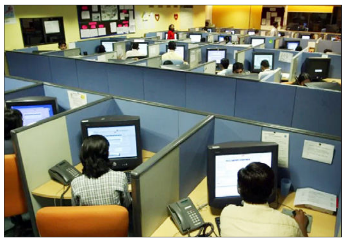

में शिकायत की कि उससे 39,200 रुपए ठगे गए हैं। शिकायकर्ता के अनुसार, उसने लॉकडाउन के कारण आमदनी कम होने पर अपने ऋण के भुगतान को स्थगित करने का अनुरोध किया था। पिछले साल नंवबर में एक व्यक्ति ने उसे फोन करके 34,000 रुपए के उसके ऋण भुगतान को 17,000 रुपए में निपटाने का प्रस्ताव रखा। शिकायतकर्ता के इस पर राजी हो जाने के बाद आरोपी ने राशि एकत्र करने के लिए एक व्यक्ति उसके घर भेजा। इसी तरह शिकायतकर्ता ने आरोपी को एक और ऋण के 1.4 लाख रुपए के बकाए के भुगतान को निपटाने के लिए 21,700 रुपए दिए। पिछले महीने उस वित्तीय कंपनी का प्रतिनिधि शिकायतकर्ता के घर आया, जिससे उसने ऋण लिया था और कंपनी के प्रतिनिधि ने उससे ऋण के बकाए का भुगतान करने को कहा। अधिकारी ने बताया कि शिकायतकर्ता ने उसे ऋण के निपटान का पत्र दिखाया, जिसके बाद यह पता चला कि यह पत्र फर्जी था। उन्होंने बताया कि पुलिस शिकायतकर्ता से धन लेने वाले एक आरोपी को पकड़ने में कामयाब रही और आरोपी से मिली जानकारी के आधार पर कॉल सेंटर पर छापा मारकर 10 अन्य लोगों को पकड़ा गया। पुलिस ने बताया कि आरोपियों के खिलाफ संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है।

पति ने पत्नी को ट्रेन से धक्का दिया, महिला की मौत

संवाददाता

मुंबई। मुंबई की लोकल ट्रेन में सफर कर रहे एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी को चलती ट्रेन से कथित रूप से धक्का दे दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। एक पुलिस अधिकारी ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि यह घटना सोमवार दोपहर को चेम्बुर और गोवंडी रेलवे स्टेशनों के बीच हुई, जिसके बाद व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया। अधिकारी ने बताया कि मानखुर्द इलाके में रहने वाला 31 वर्षीय आरोपी श्रमिक है और उसकी 26 वर्षीय पत्नी भी श्रमिक थी। दोनों का विवाह दो महीने पहले ही हुआ था। सरकारी रेलवे पुलिस (जीआरपी) के अधिकारी ने बताया कि दोनों सोमवार को पीड़िता की सात वर्षीय बेटी के साथ सफर कर रहे थे। पीड़िता की यह दूसरी

शादी थी। यह बच्ची पीड़िता की पहली शादी के दौरान हुई थी। उन्होंने कहा कि दंपति रेल के एक डिब्बे के दरवाजे पर खड़ा था। अधिकारी ने बताया कि महिला जब चलती ट्रेन से बाहर देख रही थी, तो उसके पति ने उसे पकड़ा और फिर कथित रूप से उसे छोड़ दिया, जिसके बाद वह पटरियों पर गिर गई। जब ट्रेन गोवंडी स्टेशन पर रुकी, तो उसी डिब्बे में दंपति के पास खड़ी एक महिला नीचे उतरी और उसने रेलवे पुलिस को इस घटना की जानकारी दी। अधिकारी ने बताया कि पुलिस आरोपी को पकड़कर घटनास्थल पर ले गई, जहां उसकी पत्नी घायल अवस्था में बेहोश पड़ी थी। उन्होंने बताया कि पीड़िता को अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। आरोपी को गिरफ्तार करके उसके खिलाफ प्रासंगिक धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई। अधिकारी ने बताया कि पुलिस यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि क्या आरोपी घटना के समय नशे में था या नहीं। उन्होंने बताया कि महिला की बेटी को उसके संबंधियों को सौंप दिया गया है।

केंद्र सरकार को नए कृषि कानूनों को रद्द करना चाहिए: शिवसेना

मुंबई। शिवसेना ने बृहस्पतिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आंदोलनरत किसानों की भावनाओं का सम्मान करने और नए विवादास्पद कृषि कानूनों को रद्द करने का आग्रह किया और कहा कि ऐसा करने से उनका कद और बड़ा हो जाएगा। शिवसेना के मुखपत्र 'सामना' के संपादकीय में केंद्र सरकार पर उच्चतम न्यायालय का इस्तेमाल कर किसानों के प्रदर्शन को खत्म करने की कोशिश करने का भी आरोप लगाया गया। संपादकीय में कहा गया कि उच्चतम न्यायालय के समक्ष केंद्र का यह दावा भी चौंकाने वाला है कि किसानों के प्रदर्शन में खालिस्तानी घुसे हुए हैं। उसमें यह आरोप लगाया गया, 'यदि खालिस्तानियों ने विरोध प्रदर्शन में घुसपैठ की है, तो यह सरकार की ही विफलता है। सरकार विरोध को समाप्त नहीं करना चाहती है और आंदोलन को देशद्रोह का रंग देकर राजनीति करना चाहती है।' गौरतलब है कि उच्चतम न्यायालय ने मंगलवार को अगले आदेश तक नए कृषि कानूनों के लागू करने पर रोक लगा दी और दिल्ली के बॉर्डर पर प्रदर्शन कर रहे किसानों की यूनियनों और केंद्र सरकार के बीच गतिरोध को हल करने के लिए चार सदस्यीय समिति गठित करने का फैसला किया। संपादकीय में कहा गया कि उच्चतम न्यायालय के फैसले के बावजूद इस मुद्दे पर गतिरोध जारी है।

(पृष्ठ 1 का शेष)

खतरे में धनंजय मुंडे की कुर्सी?

पवार ने एनसीबी द्वारा मादक पदार्थों से जुड़े एक मामले में राकांपा नेता नवाब मलिक के दामाद की गिरफ्तारी का संदर्भ देते हुए कहा कि संबंधित लोगों को एजेंसी के साथ सहयोग करना चाहिए। राकांपा प्रमुख ने कहा कि मलिक के खिलाफ कोई निजी आरोप नहीं लगा है। पवार ने पत्रकारों से कहा कि मुंडे ने बुधवार को उनसे भेंट करके आरोपों के संबंध में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि उनके (मुंडे) खिलाफ लगे आरोप गंभीर हैं। ऐसे में हमें इस मुद्दे पर पार्टी में चर्चा करनी होगी। मैं अपने महत्वपूर्ण सहयोगियों के साथ इस पर विस्तार से चर्चा करूंगा और उन्हें विश्वास में लूंगा। उनके विचार जानने के बाद आगे कदम उठाया जाएगा। हम यह यथाशीघ्र करेंगे। मुंडे ने संवाददाताओं से कहा कि उनके इस्तीफे के मामले में पवार और पार्टी के अन्य नेता फैसला लेंगे। गायक बनने की इच्छुक 37 वर्षीय महिला ने 10 जनवरी को मुंबई के पुलिस आयुक्त को लिखे पत्र में आरोप लगाया कि 2006 में मुंडे ने उसके साथ बार-बार बलात्कार किया। महिला ने दावा किया कि उसने पहले ओशिवरा थाने में शिकायत दी थी, लेकिन उसे नजरअंदाज कर दिया गया। बीड़ जिले से राकांपा नेता मुंडे ने आरोपों से इंकार करते हुए दावा किया है कि महिला और उसकी बहन उन्हें ब्लैकमेल कर रही है। मुंडे ने कहा कि महिला का दावा उन्हें ब्लैकमेल करने की साजिश का हिस्सा है। हालांकि उन्होंने स्वीकार किया कि वह महिला की बहन के साथ प्रेम संबंध में थे और उनके दो बच्चे भी हैं। मुंडे ने मंगलवार को जारी बयान में कहा कि उनकी पत्नी, परिवार और मित्रों को इस संबंध के बारे में पता था और उनके परिवार ने दोनों बच्चों को स्वीकार भी किया है। उन्होंने कहा कि जिस महिला के साथ उनके संबंध थे, वह 2019 से ही उन्हें ब्लैकमेल कर रही है। उन्होंने पुलिस में शिकायत भी दर्ज कराई थी और बंबई उच्च न्यायालय का रुख कर उनके खिलाफ मानहानिकारक सामग्री के वितरण पर रोक लगाने की मांग की थी।

बढ़ सकती हैं नवाब मलिक की मुश्किलें

सूत्रों की माने तो एमसीबी की जांच में यह पता चला है कि समीर खान ड्रग पेडलर करण सजनानी ट्रक सिंडिकेट में बतौर सक्रिय सदस्य काम करता था। जांच में यह भी पता चला है कि समीर करन को फंडिंग में करता था। फिलहाल एनसीबी ने समीर खान का मोबाइल जब्त किया है और उसे फॉरेंसिक जांच के लिए भी भेजा जाएगा। समीर खान की गिरफ्तारी के बाद एनसीबी ने मुंबई में कई जगहों पर छापेमारी की है। एनसीबी ने इस मामले में पहले ही राहिला फर्नीचरवाला, करन सजनानी, शाहिस्ता फर्नीचरवाला और रामकुमार तिवारी को गिरफ्तार किया है। महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री मलिक के दामाद समीर खान की गिरफ्तारी के बाद मलिक ने ट्वीट करते हुए कहा है कि कानून से ऊपर कोई भी नहीं है। जल्द ही सच्चाई सबके सामने आएगी। देश की न्याय व्यवस्था पर मुझे पूरा यकीन है। उद्धव सरकार में कैबिनेट मंत्री नवाब मलिक के दामाद समीर खान को नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने ड्रग्स मामले में गिरफ्तार किया है। एनसीबी ने बुधवार को समीर खान को पूछताछ के लिए बुलाया गया था। पूछताछ के बाद उनकी गिरफ्तारी कर ली गई। नवाब मलिक के दामाद समीर खान की गिरफ्तारी के बाद नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने मुंबई में कई जगहों पर छापेमारी की। एनसीबी ड्रग्स मामले में लगातार बीती रात से ही कई जगहों पर छापेमारी में जुटी है। समीर खान के घर पर भी एनसीबी ने छापेमारी की है। मुंबई ड्रग्स मामले में और भी गिरफ्तारियां होने की संभावना है।

महाराष्ट्र में 75% महिलाओं के पास अपने जज़्बे और जुनून के लिए हर दिन महज 30 मिनट की है मोहलत

जैमिनाई कुकिंग ऑयल्स सर्वे से हुआ खुलासा

नवी मुंबई। जेमीनाई कुकिंग ऑयल्स द्वारा हाल में महाराष्ट्र के 10 शहरों में कराए सर्वेक्षण से खुलासा हुआ है कि राज्य में 10 में से 6 महिलाएं खाना पकाने पर खर्च होने वाले समय में कटौती चाहती हैं ताकि वे अपने शौक और अपने जुनून या जज़्बे पर ज्यादा वक्त दे सकें। #IgnitingAspirations सर्वे से यह भी खुलासा हुआ है कि 40 से 45 साल के आयुवर्ग वाली 61 प्रतिशत महिलाएं अपना ज्यादातर समय घर-गृहस्थी के काम पर खर्च करती हैं, जिनमें कुकिंग और बच्चों की देखभाल प्रमुख है। ये नतीजे इसलिए चौंकाने वाले हैं क्योंकि सर्वे में शामिल 60 प्रतिशत से ज्यादा ग्राहकों का मानना है कि वे अपनी जिंदगी में सिर्फ होममेकर बनकर नहीं रहना चाहतीं। इस शोध से यह भी खुलासा हुआ है कि महिलाएं अपने परिवार के स्वास्थ्य और पोषण के पहलुओं पर ध्यान देने के महत्व को बखूबी समझती हैं। सर्वे में शामिल 65 फीसदी महिलाओं का मानना है कि उनके द्वारा पकाया गया भोजन अधिक सुरक्षित और स्वास्थ्यवर्धक होता है। लेकिन वे अपनी निजी आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए घरेलू कार्यों पर लगने वाले समय को कम करना चाहती हैं। महाराष्ट्र में 60% महिलाओं का कहना है कि वे अपने शौक तथा जज़्बे और जुनून को निभाना चाहती हैं। राज्य में नासिक, सोलापूर और पुणे तीन ऐसे प्रमुख शहर हैं जहां महिलाओं का मानना है कि रोजमर्रा के कार्यों पर 30 मिनट की कमी होने से भी उन्हें अपने शौक पूरे करने का मौका मिल सकता है। इस सर्वे से यह तथ्य भी सामने आया है कि 37 प्रतिशत महिलाएं अपने शौक वगैरह पूरे करने के लिए अपने परिवार के अन्य लोगों का सहयोग और प्रोत्साहन चाहती हैं। सर्वे के बारे में सुबिन शिवान, मार्केटिंग प्रमुख, करगिल ऑयल्स बिजनेस, इंडिया ने कहा, 'जैमिनाई ऑयल द्वारा कराए #IgnitingAspirations सर्वे के नतीजों ने उपभोक्ताओं के लिए अधिक समय उपलब्ध कराने के जैमिनाई ब्रैंड के रुख की पुष्टि की है। इस सर्वे से यह तथ्य सामने आया है कि किचन में होममेकर्स द्वारा बिताया जाने वाला समय काफी अधिक होता है और महामारी के दौरान यह और बढ़ गया है जिसका नतीजा यह होता है कि उनके पास अपने लिए उपलब्ध समय और भी घट गया है। इस स्थिति ने हमें न्यूट्री फ्रैशलॉक टैक्नोलॉजी से लैस प्रोडक्ट के रूप में लगातार इनोवेट करने की हमारी प्रतिबद्धता को और मजबूती दी है ताकि वे किचन में अपने समय को अनलॉक कर अपने शौक या जुनून पूरे करने के लिए उसका इस्तेमाल कर सकें।'

सियासी संक्रांति: बिहार में टूटी 26 साल पुरानी परंपरा, राजद-जदयू ने नहीं किया दही-चूड़ा भोज

पटना। बिहार में मकर संक्रांति पर दही-चूड़ा भोज की प्रथा काफी प्रचलित है। राज्य की सत्ता में कायम जनता दल यूनाइटेड (जेडीयू) और विपक्षी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) मकर संक्रांति के अवसर पर पिछले 26 साल से दही-चूड़ा भोज का आयोजन करती आ रही हैं। हालांकि, इस बार कोरोना महामारी के चलते इन राजनीतिक दलों ने दही-

चूड़ा भोज का आयोजन नहीं किया। जदयू के वरिष्ठ नेता वशिष्ठ नारायण सिंह ने दही-चूड़ा भोज को लेकर औपचारिक रूप से संदेश जारी किया। अपने संदेश में उन्होंने कार्यकर्ताओं को बताया कि इस बार कोरोना महामारी के चलते एहतियातन यह परंपरा नहीं निभाई गई। वहीं, हर साल आरजेडी अपने कार्यालय और राबड़ी देवी के आवास पर दही-चूड़ा भोज का आयोजन करती आती थीं, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ। हालांकि, लालू प्रसाद यादव की तरफ से मकर संक्रांति को लेकर सोशल मीडिया के जरिये एक संदेश जारी किया गया। इस संदेश में उन्होंने पार्टी के सदस्यों से कहा है कि वे गरीबों को दही-चूड़ा खिलाएं। राजनीतिक दलों ने भले ही कोरोना महामारी के चलते दही-चूड़ा परंपरा नहीं निभाई, लेकिन राजद नेता तेज प्रताप यादव अपनी मां राबड़ी देवी से आशीर्वाद लेने के बाद लोगों को दही-चूड़ा बांटते नजर आए।

मॉडल साक्षी अग्रवाल ने बताया लोहड़ी का महत्व

मॉडल साक्षी अग्रवाल ने कहा कि आजकल के लोग त्योहार तो मनाते है पर उन त्योहारों के मनाये जाने के कारण जानने में दिलचस्पी नहीं रखते। इसलिए पंजाब में जन्म लेने वाली मॉडल साक्षी अग्रवाल ने पंजाबियों के प्रसिद्ध त्योहार 13 अप्रैल को मनाये जाने की कथा यानी कारण पर प्रकाश डाला। पंजाब में दुल्ला भट्टी से जुड़ी प्रचलित लोक कथा के बारे में बताया कि मुगलकाल में बादशाह अकबर के समय में एक युवक का नाम दुल्ला भट्टी था, एक बार कुछ अमीर व्यापारी समान

के बदले लड़कियों का सौदा कर रहे थे, दुल्ले ने लड़कियों को व्यापारियों से बचा कर उन सभी लड़कियों का विवाह हिन्दू लड़कों से करवाया, तब से लोहड़ी वाले दिन दुल्ले भट्टी के नाम पर बनाया गया। लोकप्रिय गीत गाये बिना यह त्योहार पूरा नहीं माना जाता....

सुंदर मुंदरिए - हो
तेरा कौन विचारा-हो
दुल्ला भट्टी वाला-हो
दुल्ले ने धी ब्याही-हो...

साक्षी जी के अनुसार किसी भी त्योहार को मनाने का अर्थ तभी है जब उन का क्या महत्व है या था वो मालूम हो।

चंदपुर में बीडीए को नाइंसाफी नहीं करने देंगे: मौलाना अदनान रजा

चंदपुर के लोग हुजूर अदनान मिया से मिलने पहुंचे आर ए सी मुख्यालय, चंदपुर गांव के लोगों के साथ बीडीए वीसी से मिले आरएसी के लोग, जमीन की रजिस्ट्रियां दिखाई, कहा – टारगेट नहीं बनने देंगे चंदपुर के लोगों को

संवाददाता

बरेली। बरेली के बिथरी ब्लॉक में चंदपुर गांव में मुसलमानों के 80 मकानों को अतिक्रमण बताकर बीडीए ने जो नोटिस जारी किए थे, उन पर अपना पक्ष रखने के लिए गांव के लोगों के साथ अदनान मिया के निर्देश पर बड़ी संख्या में ऑल इंडिया रजा एक्शन कमेटी (आरएसी) के पदाधिकारी व कार्यकर्ता भी आज बीडीए कार्यालय पहुंचे। बीडीए वीसी से वार्ता करते हुए आरएसी के पदाधिकारियों ने कहा कि जिन मकानों को अतिक्रमण बताया जा रहा है वो बहुत पहले से बने हुए हैं जिनकी गांव वालों के पास रजिस्ट्रियां और नोटरी के कागजात जैसे सबूत हैं।

ऐसे में इन मकानों को अतिक्रमण बताते हुए इन्हें गिराना दरअसल गरीब मुसलमानों का शोषण होगा, जो आरएसी कभी बर्दाश्त नहीं करेगी। आरएसी के नायब सदर मौलाना अदनान रजा कादरी ने कहा कि हफ्ता भर पहले इसी क्षेत्र के कब्रिस्तान में 150 साल पुराने मजार पर जेसीबी चलाकर बीडीए पहले से धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचा चुका है। विरोध पर उसने मजार दोबारा बनवाने का आश्वासन तो दे दिया मगर अब उसकी नजर मुसलमानों के 80 मकानों पर जमी हुई है। उन्होंने कहा कि यह नाइंसाफी कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इसीलिए गांव वालों के साथ उन्होंने आरएसी के लोगों को भी भेजा ताकि बीडीए वीसी से मिलकर अपनी बात सही तरीके से रखी जा सके। मौलाना अदनान रजा ने कहा कि उत्तर प्रदेश सहित जिन प्रदेशों में भाजपा की हुकूमत है, वहां से मुसलमानों के घरों को टारगेट करने की खबरें आ रही हैं। उन्होंने कहा कि आरएसी यहां ऐसा नहीं होने देगी, चाहे इसके लिए कितना ही बड़ा आंदोलन चलाना पड़े। मौलाना अदनान रजा कादरी के निर्देश पर बड़ी संख्या में आरएसी पदाधिकारी व कार्यकर्ता बीडीए दफ्तर पहुंचे। प्रतिनिधमंडल ने मकानों की रजिस्ट्रियां दिखाईं और बताया कि यह मकान यहां बरसों से बने हुए हैं। अचानक नोटिस देकर और इन मकानों को अतिक्रमण बताकर इन्हें ढहाने की योजना बनाना असल में उत्पीड़न और शोषण के सिवा कुछ नहीं है, जिसे किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

बीडीए वीसी ने आरएसी पदाधिकारियों और गांव वालों को आश्वासन दिया है कि वह पूरी जांच के बाद ही कोई कदम उठाएगी। बीडीए दफ्तर पहुंचने वालो में आरएसी के मौलाना हाफि ज इमरान रजा अब्दुल हलीम खान मौलाना कमरुज्जमा अब्दुल लतीफ कुरैशी सईद रजा जुनैद खान जमाल अजहरी हनीफ अजहरी ताज खान शाहनवाज रजा फारूक रजा तहसीनी फुरकान रजा शोएब रजा उनके साथ चंदपुर के मोहम्मद यूनुस, सलीम, मुश्ताक अहमद, शकील अहमद, इब्राहीम, हिना, सलीमन, शाहीन, भूरी सहित सैकड़ों आर ए सी पदाधिकारी कार्यकर्ता वा गांव वाले मौजूद रहे।

महाराष्ट्र के लिए शुभ संक्रांति

10 महीने बाद पहली बार किसी त्योहार पर सबसे कम डेथ रेट, गुड़ी पड़वा से अब तक रिकवरी रेट 83.6 प्रतिशत बढ़ा

मुंबई। महाराष्ट्र समेत पूरा देश कल मकर संक्रांति और पोंगल का त्योहार मना गया। कोरोना संक्रमण काल के बीच तकरीबन 10 महीने बाद यह पहला ऐसा फेस्टिवल आया है, जब डेथ रेट सबसे कम यानी 2.5 प्रतिशत है। इससे कम मृत्यु दर दीपावली, भाऊ बीज और क्रिसमस पर थी। उस दौरान यह आंकड़ा 2.6 प्रतिशत था। हालांकि, सबसे ज्यादा मौतें अषाढ़ी एकादशी के मौके पर हुईं थी। उस दौरान कोरोना संक्रमितों की मृत्यु की दर 4.7 प्रतिशत थी। इस हिसाब से मकर संक्रांति महाराष्ट्र के लोगों के लिए खुशियों का त्योहार साबित हुआ है। 22 मार्च को शुरू हुए लॉकडाउन

के बाद पिछले 10 महीनों में महाराष्ट्र में गुड़ी पड़वा, अषाढ़ी एकादशी, कृष्ण जन्माष्टमी, पोला, गणेश चतुर्थी, दीपावली और भाऊ बीज जैसे प्रमुख त्योहार हुए। हालांकि, मार्च की तुलना में राज्य में लगातार रिकवरी रेट में सुधार हुआ। गुड़ी पड़वा के दिन यानी 25 मार्च 2020 को राज्य में रिकवरी रेट 11.4 प्रतिशत था, जो 14 जनवरी 2021 को बढ़कर 94.8 प्रतिशत तक पहुंच गया है।

राज्य में अभी भी 53 हजार एक्टिव केस

महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटों के दौरान 3556 नए केस मिले हैं। इसी दौरान राज्य में 3001 संक्रमित मरीज ठीक होकर घर गए हैं। इसे लेकर कुल ठीक हुए मरीजों का आंकड़ा बढ़कर 18,74,279 तक पहुंच गया है यानी कुल 94.8 प्रतिशत लोग ठीक हुए हैं।

मुंबई में 3 लाख के पार पहुंचा संक्रमितों का आंकड़ा: मुंबई में बुधवार को कोरोना संक्रमण के 675 नए मामलों के साथ कोरोना संक्रमित मरीजों का कुल आंकड़ा बढ़कर 3,00,471 तक पहुंच गया। मुंबई में पहला कोविड-19 का केस 11 मार्च 2020 को दर्ज किया गया था। आज 307 दिन बाद ये आंकड़ा 3 लाख के पार पहुंच चुका है। मुंबई में 130 दिन में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 1 लाख के पार पहुंच गया था और उसके अगले 72 दिनों में ये आंकड़ा 2 लाख तक पहुंच गया। आंकड़ों के अनुसार उसके बाद के 105 दिनों में आज ये आंकड़ा 3 लाख की संख्या को पार कर चुका है।

मुंबई में 11 हजार लोगों की कोरोना से हुई मौत: मुंबई में अब तक कोरोना महामारी के कारण कुल 11,210 लोगों की मौत हो चुकी है। 2,80,853 मरीज इस महामारी के बाद स्वस्थ हो चुके हैं। 7,525 मरीज सक्रिय हैं जिनका कोविड अस्पतालों में इलाज चल रहा है।

बुलढाणा हलचल

कोविड टीकाकरण अभियान में पंजीकृत लाभार्थियों को टीकाकरण किया जाना चाहिए: कलेक्टर एस. राममूर्ति

संवाददाता/अशफाक युसुफ

बुलडाणा। जिले में कोविड 19 रोकथाम के उपायों के तहत, कोविड19 परीक्षा, रोगियों के उपचार और कोविड 19 वायरस की रोकथाम मास्क पहनकर, साबुन से लगातार हाथ धोना और सामाजिक दूरी बनाए रखने से जिले में कोविड 19 वायरस के प्रसार को नियंत्रित करने में सक्षम हो गया है। लेकिन हमारा लक्ष्य कोविड 19 वायरस को मिटाना है।

इसे देखते हुए, जिले में चरणों में कोविशिल्ड टीकाकरण किया जाएगा। इस टीकाकरण अभियान में पंजीकृत लाभार्थियों को टीका लगाया जाएगा। हालाँकि, पंजीकृत लाभार्थियों को चरणों में टीका लगाया जाना चाहिए, ऐसी अपील जिला कलेक्टर एस। राममूर्ति ने कि है।कलेक्ट्रेट के योजना

समिति हॉल में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई। वह उस समय बात कर रहे थे। जिला स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. बालकृष्ण कांबले, निवासी डिप्टी कलेक्टर दिनेश गीते आदि उपस्थित थे। पहले दौर में, सरकारी और निजी स्वास्थ्य संस्थानों में कार्यरत जनशक्ति का टीकाकरण किया जाएगा। राज्य सरकार के सुझाव के अनुसार, टीकाकरण सत्र के दौरान जिले में सह-विन ऐप पर पंजीकृत लाभार्थियों के पंजीकरण को सत्यापित करने के लिए प्रतीक्षा कक्ष के साथ एक तीन-स्तरीय संरचना होगी, टीकाकरण के लिए एक टीकाकरण कक्ष और टीकाकरण के 30 मिनट बाद प्रतीक्षा करने के लिए एक अवलोकन कक्ष। टीकाकरण के लिए पंजीकृत लाभार्थी के मोबाइल नंबर पर टीकाकरण की तारीख, समय और स्थान का एसएमएस भेजा जाएगा। उसके बाद टीकाकरण केंद्र पर लाभार्थी के पंजीकरण की पुष्टि की जाएगी। पहचान के प्रमाण की जांच के बाद वास्तविक टीकाकरण दिया जाएगा। जिले में वैक्सीन की 19,000 खुराकें उपलब्ध कराई गई हैं। इस टीकाकरण का उद्घाटन 16 जनवरी को जिला सामान्य अस्पताल बुलदाना, सामान्य अस्पताल खामगाँव, जिले के ग्रामीण अस्पताल में होगा। राजा, उप-जिला अस्पताल, मलकापुर, शेगांव और चिखली में टीकाकरण शुरू किया जाएगा। टीका सही लिंग के शीर्ष पर दिया जाएगा। वैक्सीन इंजेक्शन ऑटो-अक्षम है। इसलिए, केवल एक ही व्यक्ति को एक इंजेक्शन लगाया जाएगा। पहला टीकाकरण के 28 दिन बाद दूसरा टीका दिया जाएगा। लाभार्थियों को दूसरी खुराक के लिए एसएमएस भी भेजा जाएगा। दूसरी खुराक के 15 दिन बाद तक, शरीर कोविडार रोग से लड़ने के लिए तैयार हो जाएगा। इसलिए टीकाकरण के बाद, कोविद निवारक उपायों जैसे कि मास्क का उपयोग, सामाजिक दूरी और हाथ धोने या स्वच्छता का पालन करना होगा।

अफवाह फैलाई गई तो मुकदमा दर्ज किया जाएगा: अगर कोई टीकाकरण के दौरान सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाता है, झूठी खबर फैलाता है या जानबूझकर टीका नकारात्मकता के साथ वायरल होता है, तो उन पर कार्रवाई की जाएगी। इसलिए किसी को भी कोविद टीकाकरण के दौरान पुष्टि के बिना सोशल मीडिया पर पोस्ट को आगे या फैलाना नहीं चाहिए। टीकाकरण एक राष्ट्रीय कार्य है और हमें इस अभियान में जिला कलेक्टर एस राममूर्ति से सहयोग करना है।

बुलडाणा में ऑल इंडिया मुशायरे 17 जनवरी को आयोजन, मोहसीन साहिल मुंबई की किताब का विमोचन

संवाददाता/अशफाक युसुफ

बुलडाणा। जब-जब इंसानियत खून बहा हो देश को तोड़ने की साजिश रची गयी हो फिरका परस्तो, जात-पात क्षेत्रवाद पर लोगों ने लड़ाई लड़ी हो या मोहब्बत, प्रेम के नाम पर किसी मजनू, का दिल तोड़ा गया हो या अपनी बेबसी पर इंसानियत ने घुटने टेक दिए हो तो वहाँ उर्दू शायरी जन्म लेती। उर्दू शायरी के तहत मुशायरें आयोजित किए जाते हैं। सजाए जा रहे है। ताकि नफरतों को मिटाकर दिलों को जोड़ा जाए। गंगा जमुनी तहजीब को बरकरार रखते हुए आज की वर्तमान स्थिति में हिंदू मुस्लिम में एकता का संदेश मुशायरों के मंच से ही दिया जा रहा है। केवल ईसी स्टेज से भाईचारे का पैगाम दिया जा सकता है। इसी सिलसिले में बुलढाणा में मोहसिन साहिल मुंबई इनकी किताब 'हुमा आफताब बिनम' का विमोचन के साथ ही ऑल इंडिया मुशायरा का आयोजन किया गया है। महेफिले मुशायरे की अध्यक्षता मारूफ शायर हसनैन आकिब खान करेंगे। किताब का विमोचन शायर डॉ गणेश गायकवाड आगाज बुलढान्वी इनके हाथों की जाएंगी। महेफिले मुशायरा 17 जनवरी 2021 दोपहर 3:00 बजे से शाम 6:00 बजे तक गायकवाड हॉस्पिटल सभागृह में आयोजित किया गया है। इस मुशायरे में जनाब हारून मास्टर, मुस्तकीम अरशद, सैयद आसिफ, निरंदर लौजेवार, मोहसीन साहिल मुंबई विशेष अतिथि रहेंगे। मुशायरे की निजामत हारुन उस्मानी भुसावल करेंगे। इस मुशायरे में आमंत्रित कवि व शायर नईम फराज, फारूक रजा, इमरान सानी, अनस नबील, मोईन गोहर, दीपक मोहल्ले, यासीन जाहिद, आकिब जमीर, स्थानीय कवि शायर रियाजअन्वर, यासीन तन्हा, आगाज बुलडान्वी, अजीम रायपुरी आसिफ राही, समिर बुलडान्वी अपना कलाम पेश करेंगे।

राजस्थान हलचल

जमीअत उलमा ए हिंद का एक ओर सराहनीय काम, श्मशान घाट हादसे में जो लोग मृत्य व जख्मी हुए थे उन लोगों की आर्थिक मदद

संवाददाता/सैय्यद अलताफ हूसैन

जमीअत उलमा हिंद का एक प्रतिनिधिमंडल श्मशान घाट हादसे में जो लोग मृत्य व जख्मी हुए थे उन लोगों की आर्थिक मदद करने के लिए मिले वहां पहुंचकर जमीअत उलमा हिंद के जिला गाजियाबाद जनरल सेक्रेटरी जनाब मौलाना असजद साहब ने मृत्यु हुए दो परिवारों को,और एक घायल परिवार को जमीअत उलमा हिंद मुरादनगर के तमाम मुसलमानों की तरफ से जो आर्थिक मदद के रूप में नीरज कुमार को 35000 नकद ओमकार को 35000 नगद निर्मल घायल 21000 नगद आर्थिक मदद दी और आगे भी मदद करने के लिए लिए कहा जमीअत उलमा हिंद के प्रतिनिधिमंडल में शामिल नगर अध्यक्ष जनाब मौलाना रिजवान साहब नगर उपाध्यक्ष हाजी मेराज सहाब जनरल सेक्रेटरी मुफ्ती असद साहब नगर कोषाध्यक्ष मौलाना खलील साहब मुफ्ती मजहर उल हक कासमी साहब मौलाना मौलाना खलील बस स्टैंड हाफिज फारूक जावेद वारसी नईम इदरीसी मंजूर सब्बाग हाजी इमरान आदि।

रामपुर हलचल

रोड पर ठेला लगाने वालों पर कार्रवाई, बाजार में मचा हड़कम्प

संवाददाता नदीम अख्तर

टाण्डा (रामपुर)। नगर के अन्दर लगने वाला साप्ताहिक बाजार जो फड़ आदि लगाने वाले मुख्य मार्ग को संकुचित कर देते हैं उसी की देखरेख में कोतवाल माधो सिंह बिष्ट सहित मय पुलिस बल के साथ सम्पूर्ण मुख्य मार्ग सदर बाजार का भ्रमण किया गया भ्रमण के दौरान कल सब्जी आदि के ठेला लगाने वालों के साथ अपना सख्त रवैयया अपना कर उनको दौड़ाया गया भ्रमण को लेकर सम्पूर्ण बाजार के अन्दर हड़कम्प मचा रहा बाद में मीना बाजार ठेकेदार वाली मस्जिद पर फड़ लगाने वालों को वहां से हटाया गया मीना बाजार में भी भ्रमण को लेकर हड़कम्प की स्थिति बनी रही अतिक्रमण करने वालों को सख्त निर्देश देते हुए कहा गया कि अगली बार यही स्थिति रही तब ऐसी दशा में अतिक्रमण करने वालों के विरुद्ध कड़ी एवं सख्त कानूनी कार्यवाही का मामला अपनाया जायेगा मीना बाजार के अन्दर फड़ आदि लगाने वालों को झण्डा चौक पर फड़ लगाये जाने की नसीहत देकर उनको वहां से हटाया गया दुकानों के सामने सामान फैलाने वालों के साथ भी अपना कड़ा रुख अपनाकर उनके सामानों को दुकानों के अन्दर रखे जाने को कहा गया। इस मौके पर कोतवाल माधो सिंह बिष्ट सहित अन्य पुलिस बल मौजूद रहा।

श्री राम जन्म भूमि समर्पण निधि अभियान, बाइक रैली का आयोजन

टाण्डा (रामपुर)। श्री राम जन्म भूमि समर्पण निधि अभियान 15जनवरी से 31जनवरी तक जन जागरण अभियान के अन्तर्गत एक विशाल बाइक रेली का आयोजन टांडा खास से शुरू होकर सीकमपुर,चक गजरौला, रामनगर लतीफपुर, खेड़ा, चक दूली, पीपली नायक, सरकथल, नारायनपुर, मुवाना, दढियल शिव मन्दिर पर बाइक रैली का समापन किया गया! जगह जगह जनजागरण अभियान रैली का स्वागत भी जोरदार तरीके से किया गया। जिसमें मुख्य रूप से प्रताप सिंह चौहान, दीपक सिंह ठाकुर, करन सिंह, राजकुमार सक्सैना,योगोश कुमार, राकेश जी, प्रीतम सिंह, जिला संचालक रामपाल सिंह हजारों की तादात में स्वयं सेवक मौजूद रहे।

शरीर को स्वस्थ रखने के साथ वजन कम करने में मदद करते हैं ये 4 डिटॉक्स वाटर

स्वस्थ रहने के लिए शरीर को डिटॉक्स करना बहुत जरूरी है। बॉडी डिटॉक्स करना यानि शरीर के अंदर के विषैले पदार्थों को बाहर निकालना। आज हम आपको ऐसे डिटॉक्स वॉटर बताने जा रहे हैं जो शरीर को टॉक्सिन्स रहित बनाने के साथ पाचन तंत्र के लिए भी बहुत फायदेमंद है। इसके अलावा इसे पीने से स्किन साफ, लिवर स्वस्थ रहता है और यह एनर्जी बूस्ट करने में मदद करता है। आइए जानिए घर पर कैसे बनाएं डिटॉक्स वाटर?

1. अनानास का डिटॉक्स वाटर - अनानास से तैयार वाटर एक्सट्रा चर्बी कम करने में मदद करता है। इसे बनाने के लिए अनानास और नींबू के टुकड़े बारीक काट लें। फिर इसे जार में लेकर इसमें पुदीने के पत्ते, पानी और बर्फ के टुकड़े डालें। अब इसे 4 घंटे के लिए फ्रिज में रख दें और फिर पीएं।

२. स्ट्रॉबरी-किवी का डिटॉक्स वाटर - स्ट्रॉबरी और किवी में विटामिन्स, पोषक तत्व भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। इससे तैयार डिटॉक्स वाटर पीने से शरीर को पर्याप्त मात्रा में न्यूट्रिशन मिलता है और यह टॉक्सिन्स निकालने में मदद करता है। इसे तैयार करने के लिए स्ट्रॉबरी और किवी के बारीक टुकड़े काट लें और इसे पानी में डाल कर इसमें पुदीने के पत्ते और बर्फ के टुकड़े डालें। फिर इसे ६ घंटे के लिए फ्रिज में रखें।

३. संतरे और खीरे का डिटॉक्स वाटर - शरीर को टॉक्सिन रहित बनाने के लिए संतरे और खीरे से तैयार डिटॉक्स वाटर काफी फायदेमंद है। यह शरीर को बीमारियों से भी बचाए रखता है। संतरे में विटामिन सी भरपूर मात्रा में होता है और खीरा शरीर को हाइड्रेट करने में मदद करता है। इससे डिटॉक्स वाटर तैयार करने के लिए पुदीने के पत्ते और खीरे को काट कर पानी में डालें। फिर इसमें संतरे के टुकड़े डाल कर फ्रिज में १ घंटे के लिए रख दें।

4.तरबूज और खीरे का डिटॉक्स वाटर - यह शरीर को टॉक्सिन्स रहित करने के साथ पाचन तंत्र के लिए भी काफी फायदेमंद है। इसके लिए तरबूज, खीरे और पुदीने के पत्ते काटकर जार में डालें और फिर इसे फ्रिज में 4 घंटे के रखें। फिर इसे पीएं।

महीने में Fairness पाने के लिए नेचुरल तरीके से बनाएं यह क्रीम

गोरापन हर किसी को अपनी ओर आकर्षित करता है। हर लड़की भी यही चाहती है कि किसी न किसी तरीके उसकी त्वचा में निखार आ जाए। इसके लिए वह कई तरह की फेयरनेस क्रीम का इस्तेमाल भी करती हैं। कई बार इन क्रीम्स में मौजूद कैमिकल त्वचा को नुकसान पहुंचाते हैं। अगर घर पर नेचुरल तरीके से फेयरनेस क्रीम बनाकर इस्तेमाल की जाए तो जल्दी फायदा मिलता है।

जरूरी सामान - 1 टेबलस्पून नींबू का रस
3 टेबलस्पून गुलाब जल
1 टेबलस्पून बादाम या ऑलिव ऑयल
2 टेबलस्पून एलोवेरा जेल

क्रीम बनाने का तरीका

सबसे पहले नींबू के रस और गुलाब जल को अच्छे से मिक्स कर लें। अब चंदन के पाउडर को इसमें डालकर मिक्स करें। इसके बाद इसमें ऑलिव ऑयल या फिर बादाम का तेल मिलाएं और अच्छी तरह मिक्सी में डालकर मिला लें। जब यह मिक्स हो जाए तो इसमें एलोवेरा जेल डाल दें और मिक्सी में सारे मिश्रण को अच्छे से मिला लें। जब यह क्रीम की तरह बन जाए तो इसे एयरटाइट डिब्बी में डाल कर रख लें।

इस तरह करें इस्तेमाल - इसे इस्तेमाल करने से पहले चेहरे को गुलाब जल के साथ अच्छी तरह से क्लीन कर लें। अब हथेली पर थोड़ी-सी क्रीम लेकर इसे चेहरे पर अप्लाई करें। इसकी चेहरे पर अच्छी तरह से मसाज करें। एक महीने तक दिन में लगातार 2 बार इस क्रीम का इस्तेमाल करें। इससे नेचुरल तरीके से चेहरे का रंग गोरा होना शुरू हो जाएगा।

कोशिश करने के बाद भी नहीं छूट रही शराब की लत तो अपनाएं ये टिप्स

आज 10 में 7 लोग शराब पीने के आदी हैं। शराब की लत ने ना सिर्फ उनकी जिंदगी बर्बाद कर दी है बल्कि उनके परिवार वाले भी इस आदत से दुखी हैं। शराब पीने की वजह से कई घर टूट रहे हैं। अपने परिवार को अच्छा माहौल देने के लिए कुछ लोग तो इस गंदी आदत को छोड़ना भी चाहते हैं। मगर कई बार कोशिश करने के बाद भी वह शराब छोड़ नहीं पाते। अगर आप शराब छोड़ने का मन बना चुके हैं तो ये घरेलू नुस्खे आपकी मदद कर सकते हैं।

1. गाजर का जूस - जो लोग शराब छोड़ना चाहते हैं उनके लिए गाजर बहुत बढ़िया है। रोजाना गाजर का जूस पीने से शराब पीने की इच्छा खत्म होती है। इसके साथ ही शरीर में एनर्जी बनी रहती है।

2. खजूर - शराब की लत से छुटकारा पाना चाहते हैं तो खजूर को दूध के साथ मिसकर करके पीएं। इसको पीने से कुछ ही दिनों में आपको फर्क दिखाई देने लगेगा।

3. करेले के पत्ते - करेले के रस से भी शराब की लत को कुछ ही दिनों में दूर किया जा सकता है। करेले के पत्तों को पीसकर इसका रस निकाल लें। फिर इसमें शहद के 2 चम्मच मिलाकर पीएं लें।

4. अंगूर - शराब जो है वह अंगूर से ही बनती है। अगर आप रोजाना अंगूर खाना शुरू कर देते हैं तो कुछ ही दिनों में शराब पीने की आदत छूट जाएगी।

5. अजवाइन - 1 गिलास पानी में अजवाइन डालकर उसको तब तक उबालें जब तक वह आधा ना रह जाए। अब इस पानी को ठंडा होने के बाद पीएं। लगातार 1 महीने तक इस पानी को पीने से शराब पीने की इच्छा कम होगी।

6. शिमला मिर्च - शिमला मिर्च को पीसकर इसका जूस निकाल लें। रोजाना खाना खाने के बाद आधा कप शिमला मिर्च का जूस पीएं। ऐसा करने से थोड़े दिनों में आपको फर्क दिखाई देने लगेगा।

7. अदरक का तेल - अदरक का तेल या इसकी चाय पीने से भी शराब छोड़ने में मदद मिलती है।

दैनिक मुंबई हलचल
अब हर सच होगा उजागर

काजोल ने बताया 'त्रिभंग' की कहानी में क्या है खास

काजोल की अपकमिंग फिल्म 'त्रिभंग' को लेकर काफी चर्चे हैं। इसमें वह ओडिशी नृत्यांगना के रोल में दिखाई देंगी। उनका कहना है कि वह इस फिल्म को रियल लाइफ से कनेक्ट करके देखती हैं। इस फिल्म का प्रीमियर 15 जनवरी को नेटफ्लिक्स पर होना है। काजोल ने बताया कि उन्हें फिल्म की कहानी पहली बार में ही भा गई थी। ऐक्ट्रेस काजोल का कहना है कि वह आने वाली फिल्म 'त्रिभंग' में अपने किरदार को जीवन के साथ जोड़ कर देख सकती हैं। 'त्रिभंग' में खास तौर से मां और बेटी के बीच के संबंधों को दिखाया गया है। अभिनेत्री रेणुका सहाणे की इस फिल्म में उस विषय को उठाया गया है, जिसपर अक्सर कोई बात नहीं करता। सामान्य तौर पर हिन्दी सिनेमा में बाप-बेटे के संबंधों पर चर्चा होती है, लेकिन मां को हमेशा दरकिनार कर दिया जाता है या उसे त्याग की मूर्ति के रूप में दिखाया जाता है। काजोल का कहना है कि वह अपने करियर को लेकर कभी कोई योजना नहीं बनाती हैं। उन्होंने कहा कि सबकुछ अच्छी स्क्रिप्ट मिलने पर निर्भर करता है।

'कृष 4' में सुपरहीरो के साथ सुपरविलेन का किरदार भी निभाएंगे रितिक रोशन!

बॉलीवुड स्टार रितिक रोशन काफी वक्त से आगामी फिल्म 'कृष 4' को लेकर चर्चा में हैं। इन दिनों उनकी इस फिल्म की तैयारियां काफी जोरों पर हैं। यह फ्रेंचाइजी बॉलीवुड की कुछ सफल सुपरहीरो वाली फिल्मों में से एक है। यही कारण है कि राकेश रोशन से अक्सर इस फिल्म को लेकर सवाल किए जाते हैं। वहीं इस फिल्म को लेकर अक्सर नए अपडेट सामने आते रहते हैं। हाल ही में इस फिल्म से जुड़ी एक खास जानकारी सामने आई है। खबरों के अनुसार, राकेश रोशन इस फिल्म को और ऊंचे स्तर पर पेश करने की योजना बना रहे हैं। इस फिल्म में रितिक को अपना ही सामना करते हुए देखा जाएगा। दरअसल, फिल्म में रितिक डबल रोल अदा करते हुए नजर आएंगे। फिल्म में जहां एक ओर वह सुपरहीरो के रूप में बुराई का नाश करते दिखेंगे, वहीं उन्हें सुपरविलेन का किरदार निभाते हुए भी देखा जाएगा। बताया जा रहा है कि रितिक का सपना था कि वे कृष में दोनों ही किरदार ब्लैक एंड व्हाइट एक साथ प्ले करें।

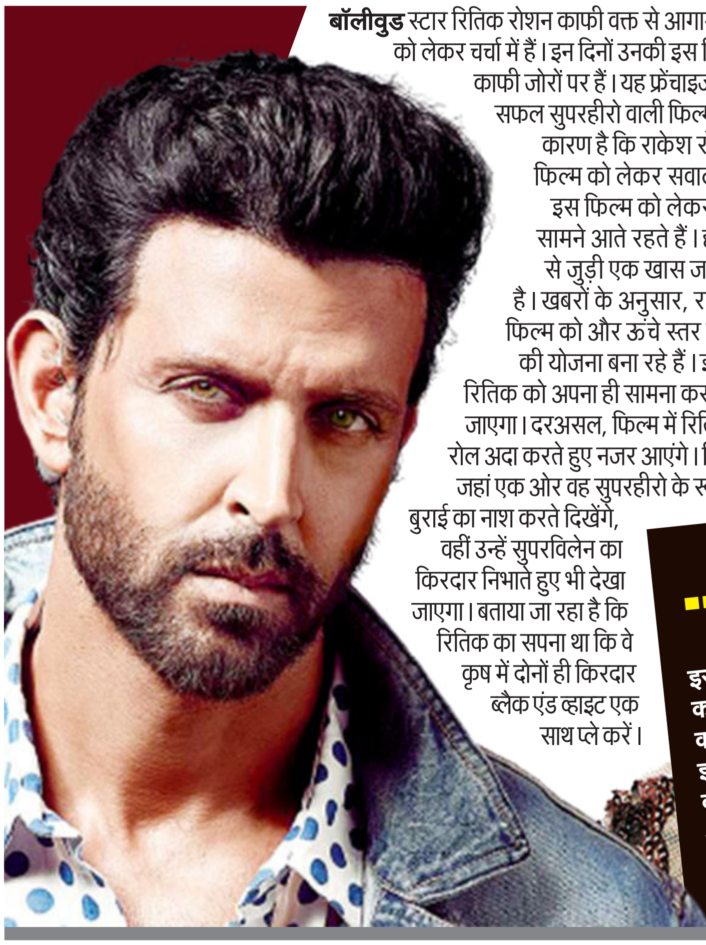

...जमकर मेहनत कर रहीं आलिया भट्ट

बॉलीवुड एक्ट्रेस आलिया भट्ट अपनी अपकमिंग फिल्म 'गंगूबाई काठियावाड़ी' को लेकर काफी समय से चर्चा में बनी हुई हैं। इस फिल्म को संजय लीला भंसाली निर्देशित कर रहे हैं। भंसाली ने इस फिल्म की शूटिंग आलिया भट्ट के साथ काफी पहले शुरू कर दी थी लेकिन बाद में कोरोनावायरस और लॉकडाउन के चलते इसे बंद करना पड़ा था। आलिया अपनी इस फिल्म के लिए काफी मेहनत कर रही हैं। सत्य घटनाओं से प्रेरित इस फिल्म में आलिया गंगूबाई के रोल में नजर आने वाली हैं। अब आलिया की इस फिल्म को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है। खबरों के अनुसार आलिया भट्ट इस फिल्म में एक बड़ी सी रैली को संबोधित करते हुए नजर आने वाली हैं जिसकी शूटिंग हाल ही में खत्म हुई है। इसके लिए संजय लीला भंसाली ने काफी बड़ा सेट बनाया था और भीड़ इकट्ठा हुई थी। बताया जा रहा है कि संजय लीला भंसाली 1960 का वो दौर दिखाना चाहते हैं जब गंगूबाई ने बड़े आंदोलन की शुरूआत की थी। जब उन्होंने सेक्स वर्कस को उनका खोया सम्मान दिलवाने की ठानी थी। इस सीन को फिल्माने के लिए आलिया भट्ट और उनकी टीम ने काफी मेहनत की है और फिल्म में ये सीन शानदार नजर आने वाला है।